DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY - *CONTD.*

MR. CHAIRMAN: Now, the debate resumes*...(Interruptions)...* Shri Deepak Prakash *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir*...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: No. Shri Deepak Prakash. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I want to say something positive.

MR. CHAIRMAN: No. Everyone has positive*...(Interruptions)...* Please, don't spoil it. Shri Deepak Prakash. *...(Interruptions)...*

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. *...(Interruptions)...* What is this? Please understand this. I am shocked. Now, Dr. Anil Sukhdeorao Bonde.

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। आज नवीकरणीय ऊर्जा के बजट में जो प्रावधान रखा गया है, उसके लिए मैं माननीया अर्थ मंत्री, निर्मला सीतारमण जी; ऊर्जा मंत्री, प्रहलाद जोशी जी तथा हमारे विकसित भारत के उद्‌गाता, यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। महोदय, कार्बन न्यूट्रैलिटी की तरफ हमें 2070 तक पहुंचना है और कार्बन न्यूट्रैलिटी अचीव करनी है।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि फॉसिल फ्यूल की वजह से जिस ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। कार्बन एमिशन, CO-2 एमिशन कम करना पड़ेगा। हम फॉसिल फ्यूल का यूटिलाइजेशन कम कैसे करें, उसके लिए जो पंच महाभूत हैं, पंच तत्व हैं, जिनमें अग्नि है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, इनकी सहायता हम नहीं लें, जो कि नैसर्गिक हैं, तो हम कार्बन न्यूट्रैलिटी की तरफ नहीं जा सकते। प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी जी ने 'वसुधैव कुटुंबकम', एक विश्व, एक कुटुंब की जो धारणा रखी है, उसमें पूरे विश्व की चिंता की है। आज जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जलवायु

---
* Not recorded.

परिवर्तन हो रहा है, इसमें पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऊर्जा के निर्माण में जो कार्बन एमिशन होता है- ऊर्जा का निर्माण तो जरूरी है, क्योंकि यदि विकसित होना है, तो ऊर्जा का निर्माण ज्यादा हो और जितनी ऊर्जा की खपत होगी, जिस देश की ऊर्जा की खपत ज्यादा है, उसी देश को विकसित माना जाता है। इसलिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। इस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में मैं आपको प्रसन्नता से बताना चाहता हूं कि हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका प्रोडक्शन 200 गीगावॉट से अधिक हो चुका है। आज देश में जो कुल विद्युत क्षमता है, उसके 45 प्रतिशत ऊर्जा का उत्पादन हम नॉन-फ्यूल से करते हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों के पहले, दुर्भाग्य से इसके ऊपर उतना ख्याल नहीं किया गया था, लेकिन इन 10 सालों में नॉन-फॉसिल विद्युत की क्षमता दोगुनी हो चुकी है। इसमें तो सौर ऊर्जा की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, हमारा देश सूर्य के ऊपर चलता है, यहाँ सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया है और 2014 की तुलना में 30 गुना बढ़कर हमारे यहां सौर ऊर्जा 85 गीगावॉट उत्पादित हुई है।

उपसभापति महोदय, विद्युत क्षेत्र के इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 3 वर्षों में पारंपरिक क्षेत्र की तुलना में अक्षय ऊर्जा की तरफ हम बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र जी मोदी जी ने जो महत्वपूर्ण कदम ग्रामीण इलाकों के गरीबों के लिए उठाया है, वह है - 4.5 करोड़ लोगों को मुफ्त घर देना। पीएम आवास योजना में वही गरीब हैं, जिनको हर महीने अपने बिजली का बिल भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। उन्हें बच्चों को तो पढ़ाना है, बच्चों के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने की दिक्कत होती है। प्रधान मंत्री नरेंद्र जी मोदी की सोच ऐसी है कि सिर्फ मुफ्त में देने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी बांटने से देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए प्रधान मंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' चालू की है, उसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। उसका स्वागत इस देश की करोड़ों-करोड़ जनता कर रही है। ...(**समय की घंटी**)... उपसभापति महोदय, समय है तो मुझे बोलने दीजिए।

श्री उपसभापतिः आप कम्पलीट कर लें, क्योंकि आपका 5 मिनट का समय था।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः उपसभापति महोदय, मैं इतना बताना चाहता हूं कि सहयोग भी बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ 2 मिनट में अणु ऊर्जा के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें सभी लोगों का सहकार बहुत जरूरी है। जब 2010 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब उसने जैतापुर के अनुप्रकल्प की घोषणा की थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हुए उसका फ्रांस के साथ करार भी हुआ, हमारे यहां की एक कंपनी का करार हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में उबाठा नाम की एक चीज है, वह उबाठा नाम की चीज, हर चीज को अपोज करती है। ये उबाठा ने जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का भी विरोध किया, जबकि जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को environment clearance भी मिला हुआ था। वह सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। उसमें एक ही साल में 16 रिएक्टर्स होने वाले थे। अभी देवड़ा जी बता रहे थे कि अणु ऊर्जा

बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो चीजें हैं कि चाहे नर्मदा सागर प्रकल्प हो, उसका विरोध किया जाए, चाहे महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग का प्रोजेक्ट हो, उसका विरोध किया जाए, अगर ये बने, तो पूरा होने के बाद उनका नाम दिया जाए, ये उबाठा जैसे लोग, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी जो नवीन चीजें लाना चाहते हैं, वे उनका जो विरोध करते हैं - उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो सबको साथ मिल कर बढ़ना होगा। जब हम सबको साथ में लेकर बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें zero neutrality की तरफ भी बढ़ना चाहिए और carbon neutrality की तरफ भी बढ़ना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से हो रहा है। इस अर्थ संकल्प में उसके लिए जो पर्याप्त निधि का प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ और उसका स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः माननीय श्री अब्दुल वहाब जी। अनुपस्थित। माननीय श्री दीपक प्रकाश जी। ...(**व्यवधान**)... माननीय जयराम जी, बहुत सारे स्पीकर्स हैं।...(**व्यवधान**)... सब लोग चर्चा सुनिए।...(**व्यवधान**)... सबको अतिरिक्त समय मिला है।...(**व्यवधान**)... माननीय चेयरमैन साहब के अनुसार इस विषय पर जो बोलना चाहते हैं, वे बोलें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है।...(**व्यवधान**)... माननीय प्रमोद जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्लीज़।...(**व्यवधान**)... कृपया इनको बोलने दीजिए।

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड)**:** माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने सदन के नेता श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे गंभीर विषय पर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया है। मैं देश की 144 करोड़ जनता का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिनके स्नेह और प्रेम के कारण दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता तीसरी बार इस देश के प्रधान मंत्री बने।

आदरणीय उपसभापति महोदय, जहाँ एक तरफ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अच्छे ऊर्जा को विकसित कर देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य है, तो वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन द्वारा की जा रही अत्यावश्यक चुनौतियों का सामना करना तथा प्रदूषण मुक्त भारत बनाने का संकल्प नरेन्द्र मोदी जी ने लिया है। देश की 144 करोड़ जनता उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। भारत का संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में पेरिस समझौता और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयास के साथ समर्थ्य है।

महोदय, भारत में बिजली उत्पादन के दो प्रमुख तरीके हैं - एक, पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा, अपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा। पहला हवा, सौर्य, जल, भूतल - इन स्रोतों से बिजली उत्पन्न करना और दूसरा, कोयला से बिजली निकालना। 2012 में भारतीय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एक अध्ययन किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि संभावित स्थलों के पास बिलजी

निकास और प्रसार की बुनियादी ढांचा कम था और इसलिए बड़े ऊर्जा प्लांट्स के लिए समर्पित प्रसार ढांचे की एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की गई और इसी दिशा में भारत की सरकार आगे बढ़ रही है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत रेन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने का केवल मिशन नहीं है, बल्कि मिशन विद विज़न है। यह प्रधान मंत्री जी का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस मिशन के तहत जहाँ एक ओर घरेलू तेल की माँग की आपूर्ति के अंतर को पाटना है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ विद्युत की हिस्सेदारी को बढ़ाने का संकल्प है।

महोदय, नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता ग्रामीण, शहरी, औद्योगिकी और वाणिज्यिक क्षेत्रों तक कैसे ले जाएँ - इस बजट के प्रावधान में यह भी संकल्प है। महोदय, 2012 के बाद से ही भारत मेजर इकोनॉमिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महोदय, भारत के प्रधान मंत्री जी ने शिखर सम्मेलन में विश्व को पंचामृत का उपहार दिया था। महोदय, हम केवल तुलना करना चाहते हैं। वर्ष 2013-14 में सामने बैठी कांग्रेस की जो सरकार थी, उस वक्त का बजट कितना था? उस वक्त मात्र 1,533.55 करोड़ का बजट था और आज 2024-25 में 19,100 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि आवंटन में 12 गुना वृद्धि है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस सरकार की नीति क्या है, नीयत क्या है तथा नेतृत्व में कितनी बड़ी क्षमता है और उस नेतृत्वकर्ता का नाम श्री नरेन्द्र मोदी है।

महोदय, यह हम सब जानते हैं कि भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता के दोहन करने का भी संकल्प है। यह हम सब जानते हैं कि परमाणु क्षमता के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन करके भारत के विकास की गति को तेज करना, इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रभावी ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने राजनीतिक रूप से फैसला लिया है कि जो 25 महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित कराना और इसके साथ-साथ उनको सीमा शुल्क से भी माफ करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार ने लिया है। यह है संकल्प और संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता, जिसको हम कमिटमेंट कहते हैं।

महोदय, हम सब यह जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा सबके लिए सुलभ बनाना है। इसको सुलभ किसके लिए बनाना है? गांवों में रहने वालों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए इसे सुलभ बनाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बिजली की उच्च लागत के कारण यह कई भारतीयों की पहुंच से बाहर हो गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने "पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना" की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट्स निःशुल्क बिजली मिलेगी, यह संकल्प है, नरेन्द्र मोदी जी का! इससे प्रत्येक परिवार को 18,000 रुपये की बचत होगी।

महोदय, इस योजना के समर्थन में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके पहले भी सरकारें थीं, लेकिन कभी भी गरीब के घर में रोशनी जलाने का संकल्प नहीं लिया गया था। गरीबों के घर में भी रोशनी पहुंचे, यह संकल्प नरेन्द्र

मोदी जी की सरकार ने लिया है और इस बजट में उसका उल्लेख किया गया है। महोदय, यह योजना देश भर में एक करोड़ से अधिक परिवारों के घरों में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हम सब जानते हैं कि विकास के बारे में अगर बात करें तो विकास का मापदंड बिजली होता है। प्रति व्यक्ति बिजली की कितनी खपत होती है, यह विकास का मापदंड है।

महोदय, अन्नदाताओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा का समर्थन और उसको प्रोत्साहित करने के बारे में इस बजट में उल्लेख किया गया है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की सरकार ने ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाने का संकल्प लिया है, ताकि मुख्य रूप से किसान के बारे में, किसानों की खेती के बारे में, किसानों की खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से फसल कटाई के मौसम में अधिक मांग के दौरान किसानों की बिजली की आवश्यकता को पूरा कर सके, यह इसकी आत्मा है और इस आत्मा में इसको संभव करने के लिए "प्रधानमंत्री कुसुम योजना" की शुरुआत की गई है। जिसके अंतर्गत 2026 तक 34.8 गीगावॉट सौर क्षमता स्थापित की जाएगी और वर्तमान बजट में इस योजना की गति बढ़ाने के लिए 1,496 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान 1,100 करोड़ रुपये की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक हैं।

महोदय, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की सफलता में भारत नेतृत्व कर रहा है। अब भारत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने आपको world leader के रूप में स्थापित कर रहा है। महोदय, प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2018 में "एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड" का संकल्प लिया था। मुझे महसूस हो रहा है कि भारत सरकार आज वह संकल्प पूरा करते हुए दिख रही है। महोदय, प्रधान मंत्री जी ने 2018 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का उद्घाटन किया था। इस गठबंधन ने सौर पी.वी. बाजार की नई क्षमता स्थापना के लिए 175 गीगावाट के साथ 2021 में अपनी रिकॉर्ड स्थिति को बनाए रखने में मदद की थी। महोदय, वर्तमान बजट में भारत को इस गठबंधन में एक प्रमुख प्रणेता के रूप में स्थापित करने के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है।

महोदय, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारत एक विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो रहा है। महोदय, पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की नीति लकवाग्रस्तता से ओतप्रोत थी। हालांकि, पिछले दशकों में सौर ऊर्जा क्षमता में 26 गुना और पवन ऊर्जा क्षमता में दोगुनी वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत अब वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। यह कोई छोटी बात नहीं है। महोदय, वर्तमान बजट में सौर और पवन ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए 16,394 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें 851 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में सतत् और रणनीतिक प्रयासों में सफलता प्रदान करेगा।

महोदय, आज भारत प्रदूषण के क्षेत्र में गम्भीरता से विचार करने वाला देश है। केवल भारत ही प्रदूषणमुक्त न बने, बल्कि पूरी दुनिया प्रदूषणमुक्त बने, यह नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है। इसलिए भारत नेट-जीरो उत्सर्जन की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने वाला 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' के रूप में अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए तत्पर है और तैयार है।

महोदय, मोदी सरकार ने भारत के पर्यावरण को de-carbonise करने के लिए 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दीर्घकालिक दृष्टि अपनाई है। इस मिशन ने वर्ष 2023 तक युवाओं के लिए छह लाख से अधिक रोज़गार पैदा करने का संकल्प लिया है और यह संकल्प नौजवानों के रोज़गार का एक आधार ही नहीं बनेगा, बल्कि भारत के विकास की गति को तेज़ करने का जो संकल्प है, यह बजट के माध्यम से हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं इस मंत्रालय के मंत्री जी, श्री प्रहलाद जोशी जी को अपनी ओर से ढेर सारी बधाइयां देता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में यह मंत्रालय बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Abdul Wahab; not present. Shri Babubhai Jesangbhai Desai.

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई (गुजरात): उपसभापति महोदय, मैं 2024-25 की रिन्यूएबल एनर्जी पर डिस्कस करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय सदस्यगण, यह महत्वपूर्ण विषय है। भविष्य के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। माननीय चेयरमैन साहब ने अनुमति दी है कि अतिरिक्त समय में जो बोलना चाहता है, उसको बोलने की इजाज़त दें। Please. ...*(Interruptions)*... बैठकर पीछे से न बोलें, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... Please. ...*(Interruptions)*... पीछे से बैठकर न बोलें, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः महोदय, आज हमारे देश को ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांति की आवश्यकता है। यह समय है जब हमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से हटकर हरित, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप वहां से न बताएं कि क्या होना है, please. Please. ...*(Interruptions)*...

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। सबसे पहले सौर ऊर्जा की बात करें, तो हमारी सरकार ने अगले पांच वर्षों में सौर ऊर्जा की क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में निवेश कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल्स की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम बड़े कदम उठा रहे हैं। पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाओं को सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, जहां पवन ऊर्जा की संभावनाएं अधिक हैं। जैव ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए हम जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देंगे। इसके लिए कृषि अवशेषों का उपयोग करके बायोगैस और बायोडीजल

उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा।

महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने ही - मैं जब 2007 से 2012 में विधायक था, तब मेरे ही समय में-उन्होंने 15 गीगावॉट का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। दूसरा, हमारे गुजरात में चारनका सोलर प्रोजेक्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर गुजरात के कच्छ में बन रहा है, इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, वैश्विक अक्षय ऊर्जा परिदृश्य में देर से प्रवेश करने वाले भारत ने 2014 से प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू किया, जो कि गुजरात में मुख्य मंत्री के रूप में उनके द्वारा विकसित सफल मॉडल पर आधारित था। इसके परिणामस्वरूप भारत की पवन और सौर ऊर्जा क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2014 में मात्र 25 गीगावॉट से बढ़कर 2024 तक 130 गीगावॉट हो गई। इसी अवधि में भारत के कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी तीन गुना बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई है। नवीनतम वित्त वर्ष 2023-24 में पवन और सौर क्षमता में अब तक की सबसे अधिक 18 गीगावॉट की वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2014-15 के अपने बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने घोषणा की, "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को बहुत उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।" इस प्राथमिकता को वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने सभी सात बजटों में जारी रखा है और नवीनतम बजट भी इसका अपवाद नहीं है।

उपसभापति महोदय, सौर सेल और पैनलों के लिए उपयोग किए जाने वाले सीमा शुल्क-मुक्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का निर्णय घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। बजट में ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि पार्सल की मुकदमेबाजी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने और निष्पादन में तेजी लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। सर, कुल मिलाकर यह बजट देश और दुनिया को आश्वस्त करता है कि भारत के शुद्ध शून्य और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर भारत निरंतर जोर दे रहा है।

महोदय, प्रधान मंत्री मोदी जी ने अपने पहले दो कार्यकालों में दूरदर्शी नीतियां, जैसे संशोधित राष्ट्रीय सौर मिशन, अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्कों में छूट, पवन और सौर ऊर्जा की अनिवार्य स्थिति, त्वरित मूल्यह्रास और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, सौर पार्क, नवीकरणीय खरीद दायित्व और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सभी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में बड़े पैमाने पर विस्तार को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं, क्योंकि भारत 2030 तक 500 गीगावॉट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम है। महोदय, हमारी सरकार की लक्षित उपलब्धियों को, जो 500 गीगावॉट के इस लक्ष्य को साकार करने के लिए अगले पांच वर्षों में लगभग 300 गीगावॉट के लिए नई पवन और ऊर्जा और क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।

3.00 P.M.

माननीय उपसभापति जी, इसका मतलब है कि अब से वार्षिक क्षमता वृद्धि 18 गीगावॉट के वर्तमान स्तर से बढ़कर 60 गीगावॉट से अधिक हो जाएगी। हालाँकि यह कठिन चुनौती है, लेकिन वित्त वर्ष 2024 में 40.56 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की नीलामी हुई, जो अब तक सबसे अधिक है।

माननीय उपसभापति जी, 2024-25 के बजट में नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारू एकीकरण के लिए pump storage परियोजनाओं के लिए नीति का भी वादा किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा हमारी सरकार भारत को हरित हाइड्रोजन विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत उदार प्रोत्साहन और वित्त पोषण के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन पावर उत्पादन के लिए अपना समर्थन स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है।

सरकार को सभी संभावित बाधाओं को दूर करने और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त समय तक काम करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र पर बजट प्रस्ताव 2030 और उसके बाद के लिए भारत के घोषित जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हैं। हमारी सरकार ने 6 जनवरी, 2022 को बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, चरण -II योजना को मंजूरी देना, जिसका उद्देश्य सात कार्यान्वयन राज्यों अर्थात् गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना है।

महोदय, गुजरात-पंजाब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरात के बनास काठा से पंजाब के मोगा तक बन रहे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से बीकानेर भी जुड़ गया है। ..(**समय की घंटी**).. करीब 1500 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के लिए 765 केवी की विद्युत लाइन डाली जा रही है। इससे छह हजार मेगावाट तक बिजली का आदान-प्रदान किया जा सकेगा। राजस्थान के बीकानेर सहित अजमेर और चित्तौड़गढ़ को भी कॉरिडोर से जोड़ा गया है। ..(**समय की घंटी**).. 765 केवी लाइन का राजस्थान में संभवतया यह पहला कॉरिडोर होगा। इसके पूरा होने के बाद बीकानेर को 400 केवी बिजली की कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई: इस पर करीब दो हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। बीकानेर को बिजली देने के लिए जलालसर में सब स्टेशन का निर्माण किए जाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों को बिजली के हब बनाने

जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। उपसभापति जी, इन कार्यों के लिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now Shri Ramji.

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यकरण पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं इसके साथ ही अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहिन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने का मौका दिया है।

महोदय, रिन्यूएबल एनर्जी भारत के लिए क्यों अहम है? मान्यवर, हमारा जो भारत देश है, उसमें 65 प्रतिशत लोग खेती या कृषि पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे क्लाइमेट में कुछ चेंजेस होते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारी खेती पर पड़ता है और हम बड़ी त्रासदी को भी झेलते हैं, क्योंकि हमें कहीं पर बाढ़ देखने को मिलती है, कहीं हैवी रेन देखने को मिलती, कहीं सूखा देखने को मिलता है, तो कहीं पर टैम्पेचर राइज देखने को मिलता है। महोदय, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न यह रहा है कि हमने गत वर्षों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पर ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे समस्याओं की निवृत्ति हो, बल्कि हम टोटली fossil fuels पर डिपेंड रहे। हमने बड़े-बड़े coal mines बनाए और इन्हें बनाने के लिए लाखों की संख्या में पेड़ काटने का काम किया। मान्यवर, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में एक हसदेव अरंड अभयारण्य था और वहाँ पर पारस माइनिंग का काम शुरू किया गया था। इसके लिए लगभग साढ़े चार लाख पेड़ काटे गए, 16,000 वनस्पतियों को नष्ट किया गया, 20 से 22 हजार जंतुओं को नष्ट किया गया और हजारों की संख्या में जलीय जंतुओं को नष्ट किया गया। वहाँ पर जो हजारों ट्राइबल्स बसे हुए थे, उन्हें वहाँ से विस्थापित किया गया, हटाया गया। साढ़े चार लाख पेड़ आदिकाल से ऑक्सीजन दे रहे थे, हमें तमाम तरह की जैव, तमाम तरह की जड़ी-बूटियाँ, तमाम तरह की चीज़ें देने काम कर रहे थे और उसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम ऐसी माइंस को डेवलेप किया। इसका परिणाम यह रहा कि आज भारत के अंदर क्लाइमेट चेंजेज़ हुए। वहाँ निकाले हुए कोयले को जलाने की वजह से जो कार्बन उत्सर्जन किया गया, उससे क्लाइमेट चेंजेज़ होते गए और आज हम तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

मान्यवर, यह सरकार की एक अच्छी पहल है कि आज हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वह विंड पावर हो, चाहे सोलर पावर हो, चाहे वह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हो। आज चर्चा का मेन विषय सोलर पावर रहा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि सोलर पावर जरूरी है, लेकिन हमारे देश में सोलर पावर अभी भी काफी कॉस्टली है। एक किलोवाट सोलर पावर बनाने के लिए एक लाख रुपये का खर्चा आता है और 12 परसेंट के आसपास जीएसटी भी लगा हुआ है, जबकि भारत के अंदर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की कमी नहीं है। जो समुद्री तटीय क्षेत्र है, उस साइड में सिलिकॉन सैंड में मिलता है। मैं सरकार से चाहूँगा कि उस क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के ऊपर भी

रिसर्च करें और उसमें यूज़ हो रहे केमिकल्स को भी जीएसटी के दायरे से बाहर लेकर आएं। सर, इसमें कुछ मॉनोपोली भी देखी गई है। इस लाइन के अंदर लिमिटेड कंपनियों का आगमन हुआ है और इसकी वजह से जो इसका प्राइस है, सोलर एनर्जी पर जो खर्चा होने वाला है, वह continuous बना हुआ है। आज भी भारत का आम नागरिक सोच भी नहीं पा रहा है कि सोलर एनर्जी के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें इस लाइन के ऊपर चाइना के बराबर काम करना पड़ेगा। आज भी 57 परसेंट सोलर पैनल चाइना से आते हैं, जिनकी क्वालिटी आज भी खराब है। भले ही, दाम सस्ता है, लेकिन क्वालिटी आज भी खराब है। हमारे पास इसमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, जो उच्च क्वालिटी का सोलर पैनल बना रही हो। इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम खुद भी अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल की मैन्यूफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तब तक यह बात पूरी नहीं होने वाली है। इसके साथ ही, सरकार को विंड पावर पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। विंड पावर इंडिया में कुछ लिमिटेड पोर्शन में ही दिखाई पड़ती है और लिमिटेड कंपनियों को ही मौका दिया जा रहा है। उनके लिए भी आपको दरवाजे खोलने की जरूरत है और साथ ही हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर भी अहम है। पूरे देश के अंदर तमाम नदियाँ हैं। हम बाढ़ के समय में त्रासदी झेलते हैं, चाहे वह बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई पार्ट हो। पीलीभीत के आसपास जो हमारा वनवसा बांध है, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लेकिन जो उसका पानी है, जो शारदा, घाघरा और कोड़ियाला नदी का पानी है, अगर जगह-जगह पर डैम बनाकर, उनका पानी रोक लिया जाए, उससे बिजली बनाई जाए और वहीं से नहर निकालकर, हम अलग-अलग क्षेत्रों में पानी का वितरण करें, तो खेती का भी काम बढ़ेगा, पानी से जो बाढ़ आती है, उससे भी छुटकारा मिलेगा और हम बिजली पर भी आत्मनिर्भर बनने का काम करेंगे।

मान्वयर, यह बात बड़ी अहम है कि जब अमेरिका जैसा देश, जिसके पास बहुत सारा क्रूड ऑइल है, कोयला भी है, आज वह फोसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को खत्म कर रहा है और धीमे-धीमे सोलर पावर की तरफ बढ़ रहा है। आज अमेरिका 23 मिलियन घरों में बिजली सीधा देने का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वह अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा सजग नजर आता है, लेकिन हम नजर नहीं आ रहे हैं। अभी बात हुई कि आवासीय घरों में छतों पर सोलर पैनल लगाने की जरूरत है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप स्कीम लेकर आए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई इसका खर्चा एक आम आदमी बिअर कर पाएगा? जब तक हम इसकी कोस्टिंग कम नहीं करेंगे, तब तक यह बात नहीं बनने वाली है। सरकार इसकी कोस्टिंग, इसकी क्वालिटी पर ध्यान दे और जो इसमें दक्ष लोग हैं, उन्हें हम कैसे एक्सपर्ट बना पाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो सपोर्ट करना चाहिए, आरएंडडी में चाहिए, हम वे सारे काम करें। इसके साथ ही, इसके ऊपर जो 12 परसेंट जीएसटी लग रहा है, उसे भी खत्म करने का काम करें। आपके माध्यम से, मेरे यही कुछ सजेशंस थे, जो मैंने आपको दिए हैं, धन्यवाद।

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Thank you, Sir, for giving me a chance to speak. I have to add two points. I will talk very briefly, not like Dr. Brittas and all. The example for this

renewable energy is shown in CIAL, Cochin Airport. Sir, Cochin Airport model should be adopted in all the airports of India. I do not know about other Governments, but Kerala Government is promoting solar energy. From my experience, I can say that we invested money in executing the solar project and, in the beginning; they were just making credits in the whole account and the balance to be paid or reimbursed. But now, they are giving only Rs. 2.5 per unit and charging Rs. 7.5 for my use. So, this sort of attitude retracts people from investing money into the solar power.

Sir, Uruguay is an example where 98 per cent of its electricity or the power is generated by renewable energy. So, we have to adopt that practice. Uruguay offers lessons in energy sovereignty and the importance of community engagement in lowering greenhouse gas emissions. Uruguay developed a supportive regulatory environment and a strong partnership between the public and private sectors as the necessary ingredients for providing population access to affordable, reliable and sustainable energy that furthers economic and social development.

Dr. Ramon Mendez Galain, a physicist who understood the potential for Uruguay's wind industry, wrote a detailed proposal for national transition to non-nuclear renewable energy, which led to Uruguay's President appointing him as the national director of energy. Sir, I advise the Ministry to see this Uruguay's pattern and do the needful. Thank you very much, Sir.

श्री उपसभापतिः थैंक यू, माननीय अब्दुल वहाब जी। माननीय प्रो. राम गोपाल यादव जी।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)ः धन्यवाद, श्रीमन्। मैं एक-दो मिनट से ज्यादा बात नहीं करूंगा।

श्री उपसभापतिः प्रोफेसर साहब, इसमें दो मिनट अधिक बोल सकते हैं।

प्रो. राम गोपाल यादवः श्रीमन्, यह जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वह बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि कभी-कभी बिजली का ग्रिड फेल हो जाता है, इसमें ग्रिड वगैरह फेल होने का डर नहीं रहता है। मंत्री जी, जो कंपनियां पैनल बनाती हैं, इस संबंध में मेरा सिर्फ सुझाव है और मैं उस पर ज्यादा कोई लेक्चर देना नहीं चाहता हूं। उनमें से कुछ इतने सब-स्टैंडर्ड होते हैं कि वे ज्यादा दिन जो गारंटी देते हैं, उतना वे चलते नहीं हैं। उन पर निगरानी की जरूरत है। दूसरे, खेती के लिए, सिंचाई के लिए और स्कूलों के लिए जो कनेक्शन लेते हैं, उन्हें कन्सेशन पर कनेक्शन दिए जाते थे, उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि उसमें कई बार एक महीना भी लग सकता है। अगर किसी किसान को जरूरत है, बिजली नहीं आ रही या किसी वजह से नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है, तो वह लगवाना

चाहता है, तो फिर उसे प्राइवेट लोगों से लगाना पड़ता है, यह मेरा अपना अनुभव है। मेरी गेहूं की फसल सूख रही थी, बिजली नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि सोलर से लगा लूं, तो यह संकट खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कन्सेशन जो है, उस पर एक महीना लगेगा, हमने कहा कि तब तक तो हमारी फसल सूख जाएगी। हमने इसे प्राइवेट से लगवाया, तो इसमें लगभग तीन लाख रुपये लग गए। इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं। आप कन्सेशन दे रहे हैं या बंद कर दिया है? आर. के. सिंह साहब दे रहे थे, अब पता नहीं कि आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ इतना ज्यादा मत कीजिए कि इसमें बहुत टाइम लगे। पैनल्स की जो क्वालिटी होती है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो बहुत ही बढ़िया कंपनियां हैं, जो स्कूलों में या किसानों को पैनल सप्लाई करते हैं या देते हैं, वे ऊंची दर पर देते हैं और वे खराब निकल जाते हैं, तो उन पर आपके अधिकारी, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नजर होनी चाहिए।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

एक बात और मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे भाषण कई लोगों ने दिए उधर से भी दिए और इधर से भी दिए, लेकिन मंत्री जी, उधर से जो आपके लोग लिख कर दे देते हैं, तो कई बार उसमें बहुत अतिशयोक्ति हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा कम करें, ताकि वह प्रैक्टिकल लगे कि यह जो कह रहे हैं, वह सही कह रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः राम गोपाल जी, मैं देख रहा था कि आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। आप मुझे नजरअंदाज कर रहे थे।

प्रो. राम गोपाल यादवः सर, मैं आपके डर से बैठ गया।

श्री सभापतिः श्रीमती संगीता यादव ।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक)**:** सर, क्या मंत्री जी का जवाब नहीं आएगा?

श्री सभापतिः उनका जवाब आएगा। क्या मैं संगीता जी को नहीं बुलाऊँ? क्या आप नारी शक्ति की आवाज को दबाना चाहते हैं? आप इधर-उधर नजर फैला लीजिए। ऐसा मत कीजिए, वे ऊपर से आपको देख रही हैं। ...(**व्यवधान**)... इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वे जयराम जी को ऊपर से देख रही हैं। ठीक है। श्रीमती संगीता यादव ।

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश)ः माननीय सभापति जी, आपने मुझे नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैं एक बार और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने महिला सशक्तिकरण का बड़े अच्छे से पक्ष रखा।

माननीय सभापति जी, यह जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा पर काम चल रहा है, यह 2014 से लगातार एक सतत प्रक्रिया के तहत ही चल रहा है। ये जो हमारे प्रयास हैं, इनसे भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा और विकसित भारत की नींव पड़ेगी। यह कोई अचानक हमारे बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया है, इसको मैं कुछ अपने तथ्यों से बताना चाहूँगी। ग्रीन ग्रोथ के लिए हमारी सरकार की एक रणनीति है, उसके तीन स्तंभ हैं - पहला है, कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाएँ; दूसरा है, कैसे हम जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करें और तीसरा है कि जो तेज गति से हमारी इकोनॉमी चल रही है, इसमें हम कैसे सबका पार्टनरशिप भी बढ़ाएँ। इसी के तहत हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, पीएम कुसम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, किसान के लिए पीएम प्रणाम योजना हो, गाँव के लिए गोवर्धन योजना हो, शहरों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग योजना हो, ये सब इसी के पाट्र्स हैं। माननीय सभापति जी, 2014 से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत सरकार ने जो भी लक्ष्य रखा है, उसको समय से पूरा किया है। पेट्रोल में 10 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को रखा गया था, वह पाँच महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 2030 से कम करके 2025-26 तक ही पूरा करने का समय रखा है।

माननीय सभापति जी, इसमें कुछ रचनात्मक सुधार भी किए गए हैं। पहला यह है कि हमारे ऊर्जा के क्षेत्र का उत्पादन हो, सही से वितरण हो और जब यह वितरण एक बार हो जाए, उसकी स्थिरता भी बनी रहे। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है। माननीय सभापति जी, 10 वर्षों में हमारी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ का निवेश किया है। इसमें ऊर्जा परियोजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऊर्जा की माँग को 2045 तक दुगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। 2030 तक 500 गीगावॉटस की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की बात भी की गई है। आज पावर मंत्रालय का जो बजट आवंटन है, वह 20,502 करोड़ रुपए रखा गया है, जो 2013-14 के आवंटन से 150 परसेंट ज्यादा है।

माननीय सभापति जी, आज ऊर्जा के क्षेत्र में हम नवीकरणीय ऊर्जा के साथ रोजगार पर भी काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हरित हाइड्रोजन सेक्टर के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए 6 वर्षों में 6 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन और प्रबंधन के लिए टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े एक लाख लोगों को ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रावधान भी किया गया है, जिसके अंतर्गत एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएँगे।

माननीय सभापति जी, हमारे प्रधान मंत्री जी बहुत विज़नरी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे अन्नदाता कैसे ऊर्जादाता बनें, इस पर प्रयास चल रहा है। कुसुम योजना उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं - कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी। कुसुम 'ए' में हम बंजर जमीन में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली का उत्पादन करेंगे, कुसुम 'बी' में हम अपने खेत में सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करेंगे और कुसुम 'सी' में सोलर पैनल लगाकर सिंचाई की व्यवस्था की गई है।

माननीय सभापति जी, अगर हम गोवर्धन योजना के बारे में बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर काम किया जाए, इसके लिए काम हो रहा है। इस बजट में सरकार ने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट्स लगाने की घोषणा की है। ये पुराने जमाने के गोबर गैस प्लांट्स की तरह नहीं होंगे। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड रुपए की राशि इस बार के बजट में रखी है।

माननीय सभापति जी, हमारी सरकार महिलाओं के लिए हमेशा चिंतित रहती है। इसके लिए solar panel installation और प्रबंधन के लिए एक लाख समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। चूँकि मैं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, तो इसमें बिना यह कहे मेरी बात अधूरी रहेगी कि जब 2014 में सरकार बनी थी और घोषणा की गयी थी कि लगातार लाइट आएगी, तो मैं उस समय विधायक थी। मैं यही सोचती थी कि 2017 में यूपी में हमारी सरकार है, सरकार ने यह बोला तो है, लेकिन यह पूरा कैसे होगा। लेकिन माननीय सभापति जी, इसके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि शहरी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति अब 2024 में 23.4 घंटे हो गई है, ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का जो अंतर 2013-14 में 4.2 था, वह अब घटकर 2024-25 में 0.1 परसेंट रह गया है। माननीय सभापति जी, मैं यह इसलिए बताना चाहूंगी, क्योंकि उस समय अगर शाम को कोई घर में आ जाता था, तो लगता था कि कैसे क्या करें। कहीं पर लाइट के बिना क्या हो सकता है? सर, चूँकि अब आपका आदेश आ गया है, तो मुझे अपनी बात को समाप्त करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन ठीक है।

श्री सभापतिः आप एक मिनट और लीजिए।

श्रीमती संगीता यादवः बस, मैं चंद लाइनें कह कर अपनी बात खत्म कर रही हूँ।

श्री सभापतिः एक मिनट और लीजिए।

श्रीमती संगीता यादवः मैं एक मिनट ही लूँगी।

माननीय सभापति जी, मैं बस इतना ही कहूंगी कि हमारे पीएम साहब लगातार हमारी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए दो लाइनें कह

कर अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ कि :

"भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है
वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है।"

मैं भी उस स्टडी का एक हिस्सा हूं।

"तुमने उस दिन परंपरा का सूरज एक उगाया था
जिस दिन तुमने संसद की चौखट शीश झुकाया था।"

सभी को प्रणाम।

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister of New and Renewable Energy, Shri Pralhad Joshi, may now reply to the discussion. Now, the hon. Minister.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं पहले तो आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में New and Renewable Energy पर चर्चा, जहां तक मैंने रिकॉर्ड उठा कर देखा है, first time हो रही है। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी, the credit goes to the Members of the House, not to me. The credit goes to the Members of the House.

श्री प्रहलाद जोशीः सर, इसमें लगभग 34 मेंबर्स ने भाग लिया है। इसमें अच्छे सजेशंस भी आये हैं और कुछ ने बिना तथ्यों के जानते हुए criticism भी किया है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो suggestions आये हैं और जो टीका-टिप्पणी हुई है, हमने सब नोट किया है, क्योंकि यह एक growing field है और नया field भी है। This is one of the most growing fields, इसलिए जो suggestions आए हैं, हम तो इसे बहुत ही positively लेंगे। लेकिन शुरुआत से, उस तरफ से instead of giving the constructive suggestions, बिना तथ्यों के आधार पर, ज्यादा ही टीका-टिप्पणी हुई है, criticism हुआ है। If there is constructive criticism, I can accept it. इसलिए मैं कुछ को उत्तर देना चाहता हूं और हमारी मिनिस्ट्री ने विगत 10 सालों में जो किया है, उसके आंकड़े और विवरण भी आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं। हम तो इस घोष वाक्य से अपनी बात शुरू करते हैं, जो हमारे ऋग्वेद से आता है..'The Universe is full of energy, living beings are alive.' *ऊर्जापूर्णम् जगत शरणम् प्राणेनाम् संजीवनम् च।* इसका अर्थ है, 'The Universe is full of energy and all living beings are alive.' इसी से प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं। जो एनर्जी यूनिवर्स में है, वह रेन्यूएबल है। उस रेन्यूएबल एनर्जी का पूरा उपयोग करना हमारा कर्त्तव्य है - ऐसा मान कर हम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। वेद-पुराण काल से ही हमने सूर्य

को भी देवता माना है, वायु को भी देवता माना है, पानी को भी देवता माना है। हम इसी प्रेरणा से काम कर रहे हैं।

जहाँ तक इस डिपार्टमेंट का सवाल है और जो कुछ भी चर्चा में आया है, उसके संदर्भ में मैं एक तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मैंने तो कल से बैठ कर सभी का भाषण सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस संदर्भ में मैं जो तथ्य रख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनें।

Sir, in 1982, a separate Department of Non-Conventional Energy Sources, DNES, was created in the Ministry of Energy to look after all aspects relating to new and renewable energy. The Department was upgraded into a separate Ministry, that is, the Ministry of Non-Conventional Energy Sources, MNES, in 1992, and it was renamed as Ministry of New and Renewable Energy in 2006. इसमें अभी-अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने ग्रीन हाइड्रोजन को एड किया है, बाकी जो काम हैं, जैसे Development and Promotion of New and Renewable energy, including, solar, wind, bioenergy, small hydro, tidal, geothermal - ये सब इस मंत्रालय के तहत आते हैं। Research and Development regarding the new and renewable energy, अभी तो ग्रीन हाइड्रोजन एड हुआ है। The matter relating to energy storage, decentralized renewable energy applications और उसके साथ-साथ Renewable Energy Development Agency, IREDA, Solar Energy Corporation, SECI- ये सब इस मंत्रालय के तहत आते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि काँग्रेस पार्टी, यूपीए और इंडी ब्लॉक गठबंधन के कई लोगों ने बहुत टीका-टिप्पणी की है।...(**व्यवधान**)... इंडी के बाद जो 'ए' होता है, वह साइलेंट होता है, इसलिए हम इंडिया एलायंस नहीं बोल सकते हैं, इंडी एलायंस ही करेक्ट है।...(**व्यवधान**)...

Sir, as I said, the Department was formed in 1982; the Ministry was formed in 1992. From 1992 till date, जो हुआ, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 2004 से 2014 तक, in the entire world, when the renewable energy was discussed, developed, काम शुरू हुआ था, तब हमारे देश में इनके कालखंड में उस दस साल में total expenditure 6,091 करोड़ रुपए का हुआ था, whereas, हमारा सिर्फ इस साल का बजट 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। साथ ही साथ, मोदी जी के 10 ईयर के कालखंड में हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर 36,952 करोड़ का हुआ है। सर, मैं आपकी अनुमति से स्कीम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, पीएम-कुसुम योजना, National Green Hydrogen Mission, Viability Gap Funding Scheme for offshore wind energy projects, PLI for High Efficiency Solar PV Models आदि जो स्कीम्स हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा में ऑलरेडी आर्डर प्लेस हुआ है और सारी स्कीम्स को मिलाकर टोटल अमाउंट 1,60,000 करोड़ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके कालखंड में 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000 का एक-एक स्कैम होता था और मोदी जी के कालखंड में सिर्फ MNRE में 1,60,000 का स्कीम हो गया है। आप तो स्कीम और स्कैम के डिफरेंस को समझते हैं! ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Only what the Minister speaks will go on record. ...*(Interruptions)*... Only what the hon. Minister speaks will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing except what the hon. Minister says will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रहलाद जोशी: सर, यहां प्रॉब्लम यह है कि वे कुछ भी बोल सकते हैं। जब हम रिप्लाई देना शुरू करते हैं, तो इनमें सुनने की क्षमता नहीं रहती है। यह प्रॉब्लम है, सर। ...(**व्यवधान**)... जिसके नाम का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप ऐसा मत कीजिए। सर, मैं जयराम जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Only what the hon. Minister speaks will go on record, till he concludes. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रहलाद जोशी: सर, अभी-अभी तेलंगाना में A1, A2 की बहुत चर्चा हो रही थी। मैं उसमें एक्चुअली में नहीं जाना चाहता था, लेकिन हमको ये उकसा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, ये जो A1, A2 की बात कर रहे हैं, तो तेलंगाना में अभी-अभी, just recently, two-three months back इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वह किसने दिया है? ...(**व्यवधान**)... गलत क्या है, आपकी सरकार ने दिया है। यह तो पूरा रिकॉर्ड पर है, आपकी सरकार ने दिया है। ...(**व्यवधान**)... सर, केरल में...

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, आपने क्या कहा, मेरी तो समझ में नहीं आया।...(**व्यवधान**)... मेरी समझ में नहीं आया कि वास्तव में यह क्या है।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, तेलंगाना में A2 को ...(**व्यवधान**)... A1, A2, वे जो भी बोलते हैं, उनकी भाषा में मैं उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि आपने नाम लेने से मना कर दिया है और यह उनको भी मना है और हमको भी मना है। सर, ये ही लोग देते हैं और हमारे ऊपर बोलते हैं। सर, यहां लक्ष्मण जी बैठे हैं। इन्होंने तेलंगाना में दिया है या नहीं दिया है। ...(**व्यवधान**)... केरल में पहले कांग्रेस ने दिया और कम्युनिस्ट ने उसको कंटिन्यू किया, तो हाथी के दांत के बारे में कल बताया था न, यही है हाथी के दांत। ...(**व्यवधान**)... मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, हाथी के दांत। ...(**व्यवधान**)... हाथी के दांत, दिखाने के अलग और खाने के अलग। ...(**व्यवधान**)... Sir, the Ministry of New and Renewable Energy is working in line with the vision of *Panchamrit* commitments of the hon. Prime Minister at CoP26. The hon. Prime Minister has outlined a vision for energy transition of India at the 26th session of the Conference of Parties, 2026 at Glasgow known as *Panchamrit*, which is to reach 500 Giga Watt of non-fossil energy capacity by 2030. इसमें भी प्रश्न उठे हैं कि कैसे करेंगे, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। How are we going to achieve further, I am going to explain it. पंचामृत में हमारा टारगेट है 50 per cent of power generation

installed capacity from non-fossil sources by 2030, reduction of total projected carbon emission by 1 billion by 2030, reduction of emission intensity of the economy, that is GDP, by 45 per cent by 2030 over 2005 levels and achieving target net zero emission by 2070. This is the target and this is the *panchamrit*. In line with hon. Prime Minister's announcement, our Ministry is working towards achieving 500 gigawatt installed electricity capacity from non-fossil fuel by 2030. मैं बाद में वह explain करता हूं, how we are going to achieve it. जो सरकार की 9 priorities हैं, उनमें energy security भी है। The Budget allocation, as I already told, last year, was Rs.10,000 crore and this year it is Rs. 20,000 crore; all carry forward, सब मिलाकर, it is Rs.21,330 crores. The Ministry of New and Renewable Energy has six umbrella schemes. One is solar energy, bio-energy program, program for wind and other renewable energy, supporting program, hydrogen mission, storage and transition. There are other schemes. One is PM-Suryaghar. Initially, it was grid connected rooftop scheme. Now, it is subsumed in PM-Suryaghar and the total budget allocated, both capital and revenue together, is Rs. 21,230 crore. I thank hon. Prime Minister and Finance Minister for such a huge allocation. While we are in the process of implementing it, this will create employment opportunity in the renewable sector at the local level, reduce the dependence on fossil fuel, migrate the climate change, enhance the energy security, reduce the carbon emissions and promote the sustainable development. मैंने पहले भी एक sentence में ज़िक्र किया है, अभी मैं थोड़ी detail में जाना चाहता हूं, I am happy to share that in the last one decade, from 2014 to 2024, under the visionary leadership of the Prime Minister, the installed renewable energy capacity has increased 165 percent; from 76.38 gigawatt in 2014 to 2,003.1 gigawatt as of now. For the first time, as I have said, we have crossed 2000 gigawatt. During the last 10 years, the installed solar energy capacity has increased from 2.82 gigawatt in March 2014, to 85.47 gigawatt in June, 2024. It is an increase of around 30 times. During the last 10 years, wind energy was 21 gigawatt. Today, it is 46.66 gigawatt. The share of thermal sources in the total installed capacity has come down from 67.69 gigawatt in 2013-14 to 54.46 gigawatt in 2024. Share of non-fossil fuel in the total installed capacity has increased from 32.20 to 45.54. सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हुआ है, उसको appreciate करना है। उसके बाद suggestion देते हैं, तो आप 60 साल तक पावर में थे। हम तो स्वीकारते हैं, लेकिन इनकी problem यह है कि जब थर्मल का जमाना था, तो पहले उत्पादन नहीं करते थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी, एक मामले में इनका experience आपके मुकाबले नहीं है। आपको उधर बैठने का ज्यादा experience है।

श्री प्रह्लाद जोशीः जी, हमें उधर बैठने का ज्यादा experience है, लेकिन अभी हम आगे जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में इधर ही बैठेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, जब thermal का जमाना था, घोटाला किया और इसके साथ ही साथ we had the fourth largest reserve of coal, but coal extraction नहीं हुआ, हम import करते थे। सर, import-based power plant बनाए थे, लेकिन आज we have doubled the production of coal. आज का समय new and renewable energy का है, लेकिन दस साल इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। इन्होंने 6,000 crore rupees का expenditure किया। ये लोग आज हमसे प्रश्न करते हैं, हमें पाठ पढ़ाते हैं।

SHRI JAIRAM RAMESH: *

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record except what the Minister says.

श्री प्रह्लाद जोशीः सर, † अभी coal import का total substitutable coal import next year से बंद होगा। मैं previous कोल मंत्री के नाते कह रहा हूं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि the total RE generation in India has increased from 193.50 billion units (BU) in 2013-14 to 359.89 BU in 2023-24. This is Narendra Modi.

Now, I come to solar power tariff. एक तो मॉडल नहीं बना रहे हैं, PV model नहीं बना रहे हैं, cell नहीं बना रहे हैं। इसमें हमने जो काम किया है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। इन लोगों के कालखंड में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए दुनिया से सब कुछ import होता था। इसके कारण the solar power tariff was almost Rs.11 per unit in 2010-11. आज यह है कि हमने जो PLI किया है, हमने जो 'Make in India' किया है, इसका स्तर बढ़ाया है, volume बढ़ाई है। मोदी जी के नेतृत्व में Today, it is Rs.2.60 per unit in 2023-24. And, I am proud to share today that, हम सबके लिए गर्व की बात है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, नरेन्द्र मोदी और एनडीए के लिए नहीं, India is at the fourth position globally in renewable energy installed capacity, and we are the fifth largest economy of the world. Further, we stood fourth in the matter of wind power capacity and fifth in solar PV capacity.

Now, the installed capacity in solar power as on date is 85.4 GW. Under implementation, जो tender हुआ है, उसका 100.40 GW है। सब कुछ order हुआ है। अभी-अभी जो tender हुआ है, वह 74.34 GW है। Total capacity, which is in the pipeline, is 256.02 GW.

* Not recorded.

† Expunged as ordered by the Chair.

आपको तो आशा रखनी है। आपके दस साल में तो निराशा ही निराशा थी। आज तो आशा का माहौल है, हम करके दिखाएंगे और आज 200 किया है, आगे मोदी जी के नेतृत्व में 500 भी करके दिखाएंगे। जब 2030 आएगा, तो भी आप उधर रहेंगे और हम इधर रहेंगे। उस समय जो मंत्री रहेंगे, वे स्टेटमेंट देंगे कि हमने 500 अचीव किया है। ऐसा स्टेटमेंट आएगा और इसी सदन में आएगा। आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह मुझे पता नहीं है। ..(**व्यवधान**).. Sir, in the wind power, installed capacity is 46.6 GW, and, under implementation is 20.81 GW. Tidal is 1.70 GW and total is 68.93 GW. In Hydro, as on date, installed capacity is 51.93 GW and under-implementation is 17.25 GW. Total is 69.18. Including nuclear, non-fossil से आज के दिन, पाइपलान में टोटल 427.56 GW है। आप उम्मीद रखिए - यदि आपके करने से नहीं हुआ, हम भी नहीं कर सकते, मोदी जी नेतृत्व में नहीं होगा - आप ऐसा मान कर मत चलिए - क्योंकि मोदी है, तो मुमकिन है। Sir, India has witnessed significant shift in the investment dynamics of renewable energy projects. During the last 10 years, around seven lakh crores of rupees have already been invested. इनके काल खंड में पूरा मिलाकर 3 लाख भी नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ दस साल में 7 करोड़ हो गया है।

Further to set up the non-fossil fuel-based capacity of 500 GW, 30 lakh crores की expectation है। महोदय, मैं एफडीआई के बारे में बाद में बताऊंगा, मैं अभी न्यू इनिशिएटिव्ज के बारे में बताता हूं। The Union Cabinet has approved the Viability Gap Funding in the offshore wind energy projects with total outlay of Rs. 7,453 crore for installation of 1000 MW offshore wind energy projects, 500 each on the coasts of Tamil Nadu and Gujarat. The upgradation of two ports to meet the logistics requirements of the offshore wind energy projects, the Ministry of New and Renewable Energy is implementing the National Green Hydrogen Mission. In this also, our overall outlay of the Viability Gap Funding is Rs. 19,744 crores. The overarching objective of the Mission is to make India a global hub for the production, usage and the export of the Green Hydrogen and its derivatives. To facilitate large-scale adoption of the rooftop solar scheme, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched on 29th February, 2024. सर, यह कार्य अभी हुआ है।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

शायद असम से हमारे बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य जी अभी बोल रहे थे कि लद्दाख में कुछ कीजिए। MNRE has planned to set up 13,000 MW renewable energy along with 1200 MW battery energy storage system in Ladakh. An inter-State transmission system would be set up because Ladakh is highly potential. As far as solar energy is concerned, it has technically very high solar irradiation. For lower evacuation and grid integration, 13 GW RE projects

in Ladakh and dispatch of power from UT of Ladakh and other parts of the country, हमने इसमें भी व्यवस्था कर रखी है।

MNRE is implementing PLI scheme for the high efficiency of solar PV models with the outlay of 24,000 crore of rupees. Under this scheme, Letter of Awards has been issued. Letter of Awards have been issued in November-December, 2021 and April, 2023 for setting up of 48,337 MW, fully or partially integrated manufacturing capacity of high efficiency solar modules. The manufacturing capacities awarded are scheduled for commencing from October'24. सर, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। आज अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर में आ जाएगा and April'26. हमने बहुत पॉलिसी रिफॉर्म्स भी लिए हैं, उसके बारे में बोला था कि इसे 500 कैसे करेंगे। Notification trajectory of RE power bids of 50 gigawatts per annum is to be issued by Renewable Energy Implementation Agency, that is, Solar Energy Corporation of India, National Thermal Power Corporation, NTPC, National Hydro-Electrical Power Corporation, Satluj Jal Vidyut Nigam. That is from 23-24 to 27-28. हमने इन्हें बताया है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि they have to call for the bids for 50 gigawatts every year. Foreign Direct Investment is permitted up to 100 per cent under the automatic route. कल कई माननीय सदस्य फोरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे थे। Regarding waiver of interest rate, interstate transmission system charged for the interstate sale of solar and wind power project to be commissioned by 30th June, 2025. For green hydrogen projects till December, 2030 and offshore wind projects till December, 2032, to boost the renewable energy purchase obligation, RPO trajectory has been issued and notification has been issued. Now, Renewable Energy Purchase Obligation is mandatory for every Discom. A project development cell has been set up. It is already there. Standard bidding guidelines have been issued. मैं आपको प्रधान मंत्री पीएम कुसुम योजना के बारे में बताता हूँ। मैं पीएम सूर्य घर बिजली योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। To bring relief to the common man, this year, the Prime Minister has launched PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please.

श्री प्रहलाद जोशी: जब आप भाषण दे रहे थे, तब मैंने पूरा सुना था। अब आपको भी सुनना पड़ेगा। As on 13 February, 2024, installed rooftop solar panels of one crore household were there with the outlay of Rs. 75,021 crores. This scheme has overwhelming response from the residential households. Till July, 2024, more than 1.30 crore individuals have registered, more than 15 lakh consumer applications have been received and around 2.3 lakh solar roof top systems have been installed. फरवरी लास्ट में शुरू हुआ, मार्च में इलेक्शन थे, अप्रैल में

इलेक्शन थे, मई में इलेक्शन थे, जून-जुलाई से लेकर आज दो महीनों में 2.3 lakh solar roof systems have been installed. The scheme stands globally as a monumental effort with one of the world's most impactful and the biggest initiatives of renewable energy. Through the scheme, households will be able to save electricity bills as well as earn additional income through the sale of surplus power to the discoms. अब मैं आपको यह एक्सप्लेन करता हूँ कि यह कैसे फ्री होता है। Sir, up to 2 KV, Rs. 60,000 is the subsidy. For third KV, it is Rs. 18,000. We can maximum go up to Rs. 78,000 for 3 KV. जो हमारे पास 7,000-odd empanelled vendors हैं, हम यह भी मॉनिटर करते हैं, the maximum price should be between Rs. 1,50,000 to Rs. 1,60,000 for total 3 KV. अगर आप 1 लाख, 60 हज़ार लें, तो भी 78 हज़ार, लगभग 50 परसेंट हम सब्सिडी दे रहे हैं। Without collateral security from nationalised banks 7 per cent interest में इनको लोन मिलेगा। अगर 80 हज़ार लोन लेते हैं, तो भी the total EMI for ten years will be Rs.610 to Rs.625. Monthly household, जो national average है, उसके हिसाब से लेते हैं, तो उनका मंथली बिल टोटल 1,875 रुपये आता है। अब वह बिल तो नहीं आता है। 1,875 रुपये मंथली बिल है, तो उसमें पूरा माफ हो गया। उसमें बैंक को 610 रुपये ईएमआई देते हैं। Net Metring System है, उसमें अगर आप deduct करते हैं - वे हर महीने on an average 1,875 रुपये देते थे, मैं देश का एवरेज़ बता रहा हूं, उसमें net monthly benefit will be Rs.1,265 and normally 3 केवी के लिए 300 units will be generated in normal course. पांच लोगों के एक घर में 300 यूनिट्स कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। ये अपोज़ीशन वाले जहां भी रूल कर रहे हैं, वहां उन्होंने 200 यूनिट्स कहा, लेकिन 200 यूनिट्स कभी भी नहीं दी, 50-60 यूनिट्स ही दी हैं, लेकिन इसमें 360 यूनिट्स जनरेट होती हैं। अगर वह 250 यूनिट्स यूज़ करता है, तो भी nearly about 90-100 यूनिट्स he can sell to the Discom. Now Renewable Purchase Obligation (RPO) has been notified and has been made mandatory. Otherwise, Discoms will be penalised. पहले तो यह toothless था, इसीलिए कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता था। इस कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, for a family of 4-5 persons, the maximum units will be 200-250 units. The remaining units he can sell. And by doing that, he can earn also. जब चुनाव आता है, तो ये लोग 200 यूनिट्स देने की बात करते हैं और अंत में देते कितना हैं? जब मैं राजस्थान का प्रभारी था, तो मेरे साथ अरुण सिंह जी भी थे, उस समय इन्होंने सभी जगह यही एनाउंस किया और वहां इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई। इन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के चक्कर में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से ही फ्री कर दिया। In normal course, this panel's life is more than 25 years. अगर आप 25 साल लेते हैं, then for 15 years, it will be entirely free. सर, यह तो sustainable model है। जहां फ्री एनाउंस किया, वहां इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पूरा ठप्प हो गया। आप इसे उपयोग कीजिए, इसमें आपको लाभ होगा। अभी Renewable Purchase Obligation (RPO) मेंडेटरी है। इसीलिए यह कैसे फ्री है - कम से कम जो शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से सुन रहे हैं, उनको तो समझ आया है, ऐसा मैं मानता हूं। ...(**व्यवधान**)... The subsidy of Rs.430 crore has already

been directly transferred into the bank accounts of beneficiaries in two months. We should all appreciate it and communicate it. Subsidy of Rs.430 crore has already been directly transferred into the bank accounts of beneficiaries in two months. The scheme will result in addition of 30 gw solar capacity through the rooftop solar panel in the residential sector generating one lakh crore units of electricity and resulting in reduction of 720 mmt of CO2 emission over 25 years.

4.00 **P.M.**

कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सिर्फ CO2 का लक्ष्य रखने से कुछ नहीं होगा। इसमें तो समग्रता से सोचना चाहिए। जो इसका उपयोग करते हैं, उनको भी benefit होना है; nature को भी benefit होना है, अगर हम यह सोच कर काम करते हैं, तो यह काम आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 100 परसेंट ठीक तरह से देखते हैं, अगर चश्मा निकाल कर देखते हैं, तो आपको दिखेगा how good it is. अगर आप ऑपोज़िशन, politics का चश्मा पहन कर देखते हैं, तो आपको नहीं दिखेगा। ...(**व्यवधान**)...

The second one is the National Green Hydrogen Mission. जब भी technology के adoption की बात आती है, दुनिया 40-50-60 साल से उसका उपयोग करके, invention करके, discover करके उसको अपनाती है, लेकिन भारत में उसका काम शुरू होता है, सर, मैं गर्व से कहता हूँ, यह देश के लिए भी गर्व है, हम सब लोगों के लिए गर्व है, when the so-called developed countries have started the work of Green Hydrogen Mission, उससे पहले भारत में मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, the last week itself. इसीलिए मैंने चेयरमैन साहब और सदन को धन्यवाद अर्पित किया है कि पहली बार इसकी चर्चा हो रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, इसको authenticate करना चाहिए।

श्री प्रहलाद जोशीः हाँ, हाँ, मैं authenticate करता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No cross-talk please. *...(Interruptions)...* माननीय मंत्री जी, आप इधर देखिए, प्लीज़।

श्री प्रहलाद जोशीः पार्लियामेंट में last week एक question उठाया गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय जयराम जी, आप बीच में न बोलें। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRALHAD JOSHI: The National Green Hydrogen Mission was launched on 4th January, 2024, with an initial outlay of Rs.19,744 crore up to 2029-30. This has become possible only because of the visionary leadership of Prime Minister, Shri Modi. मोदी जी का नाम सुनते ही इनको दर्द उठ जाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, बैठ कर बात न करें।

श्री प्रहलाद जोशीः सर, मैं आपको Green Hydrogen Mission के बारे में बताता हूँ।

श्री उपसभापतिः प्लीज़, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... डा. साहब, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... आप बताएँ। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, what I said is that out of a total of about Rs.19,000 crore, an amount of Rs.17,490 crore is for green hydrogen project and the remaining amount is for manufacturing of electrolysers. In the SIGHT scheme, Strategic Intervention and Green Hydrogen Transition, in Component-1 for manufacturing of electrolysers, tender हो गया है, award हो गया है। It is awarded. जयराम जी, आप सुनिए, it is awarded. Work has started. *...(Interruptions)...* आप आ जाइए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आपस में बात नहीं करें। ...(**व्यवधान**)... सिर्फ माननीय जोशी जी की बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी और कोई नहीं, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRALHAD JOSHI: Green Hydrogen Mission Component-2 का tender भी हो चुका है, bid final हो चुका है। ...(**व्यवधान**)... मैंने बताया कि ए-1 को कहाँ-कहाँ दिया है। केरल में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, वह सब मैंने बताया और मैं इसे बार-बार नहीं बोलना चाहता हूँ। राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, तब क्या हुआ, वह भी मैं बोलता हूँ। राजस्थान में उनको बुला-बुला कर भाई बोला था और क्या बोलना है!

सर, SIGHT Component-1 में Tranche-I में 1,500 megawatt was awarded to eight companies. In SIGHT Component-2 Tranche-I, 4,12,000 tonnes per annum, इसमें green hydrogen का allotment हो चुका है। In Tranche 2, tender for 4,50,000 tonnes per annum is ripe. In mode 2 of component 2, for green ammonia for the fertilizers, which is equivalent to 1.3 lakh tonnes of hydrogen, process is on. इस प्रकार से काम हुआ है। यह अलॉट हो गया है, काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा और दुख यह होगा कि इतना काम कैसे हो गया, क्योंकि आप तो appreciate नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, the success story. Just to

give a glimpse of the success of this initiative, let me inform my esteemed colleagues that we have completed the bidding of Tranche 1 allocating 4.12 lakh tonnes per annum green hydrogen. We are in the process of awarding 7.5 lakh tonnes per annum. सर, मैं आपको बताता हूँ कि first Tranche पर 4.12 lakh tonnes जो already allot हुआ है, in that, 50 per cent quantity has already been booked. That is, 2 lakh tonnes per annum green hydrogen is tied up to be exported to the global companies thus realizing our vision for 'Make in India, Make for the World'. That has already been done.

सर, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि many of the States like Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh have initiated the process of encouraging the green hydrogen project. Through you, I appeal to the other States. इसमें तो politics नहीं करना है। Green hydrogen के projects आपके यहाँ आएँगे। इसके लिए हमारा support है। इसलिए मैं यह appeal करता हूँ कि आप policy बना दीजिए। आपके यहाँ policy बनने के बाद वहाँ projects आएँगे। तो over all, जो green hydrogen का विषय है, इस पर अभी दुनिया में भी बहुत काम हो रहा है और भारत में भी हो रहा है और future is the green hydrogen. तो इसीलिए हम सब लोगों को मिल कर काम करना है। तो हमारे shipping sector में pilot project के रूप में some of the ships run through the green hydrogen. We have allocated Rs.115 crores. For steel sector, we have a pilot project of Rs.455 crores. It is already alloted. We have also outlaid the pilot project of the transport sector for Rs. 496 crores till 2025-26. So, this is about the green hydrogen.

सर, प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान - इसके बारे में बहुत चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि इसमें किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम सबको मिलकर काम करना है। PM-KUSUM was launched in 2019. It has been scaled up in November, 2020 and January, 2024. This scheme was launched to benefit the farmers' community to provide financial support to the farmers for installation of standalone solar pumps. इसमें component A है, component B है और component C है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि first of all, PM-KUSUM is demand-driven. The implementation of beneficiary selection and commissioning of the plant is responsibility of the State implementing agency. After Renewable Purchase Obligation (RPO), demand has started now. मैं आपको बताना चाहता हूं कि component C में, जो आप चर्चा कर रहे थे, component C में कर्णाटक से हमारे पास 1,79,588 pumps का डिमांड आया। अगर project fail है, तो यह क्यों आता? ठीक है, शुरुआत में कोविड भी था, बाद में RPO नहीं था, अभी RPO हो गया है। कर्णाटक में आज के दिन तो हमारी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर वहाँ project fail फेल हो रहा है, तो आपकी पार्टी की सरकार ने हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में डिमांड क्यों भेजा है? They have sent the demand officially. तेलंगाना ने भी भेजा है, why? It is because, now, people are feeling that it is going to be successful and

that is needed. So, basically, we should understand this. Component-A में तेलंगाना ने 4,000 मेगावाट का डिमांड किया है और Component-C में apart from Karnataka and Telangana, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, all the States have demanded. Component-B में हमें overall जो demand मिला है...., Component-C में हमने already 35 लाख पम्पों के लिए सोचा था, लेकिन उसके अलावा 28 लाख एक्स्ट्रा पम्पों के लिए हमें officially request भेजा गया है, because I am quite confident that this is going to be most successful. But, 'Yes', थोड़ा delay हुआ है। स्टेट्स ने इसको implement करने में delay किया है। States implementation में delay क्यों किया? डिले इसलिए हुआ कि एक तो RPO नहीं था, दूसरा, कई जगहों पर electricity फ्री कर दिया गया है, इसलिए farmers इसके तहत इसको लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट्स, जहाँ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार नहीं है, वे भी यह समझ रहे हैं कि sustainable model यही है। इस तरह से PM-KUSUM भी आगे बढ़ रहा है। This is a demand-driven project which we should appreciate and understand. इसलिए यह भी success होगा और सक्सेस हो रहा है। इसके तहत हमारे पास already ज्यादा demand आया है। इसके साथ-ही-साथ एक और स्कीम है और वह है Offshore Wind Energy Programme. आज से 30 साल पहले offshore wind energy के बारे में कई देशों ने सोचा और उस पर काम भी शुरू किया। यह यूरोपियन कंट्रीज़ में है, इंग्लैंड में है, लेकिन भारत में इस पर काम नहीं हुआ था। हमने इस पर भी काम शुरू किया है, क्योंकि India is blessed with a coastline of 7,600 Kilometres surrounded by water on three sides and has a good potential for the offshore wind energy generation. इस तरह के un-tapped energy को tap करने का निर्णय करके Modi-led Government, the Ministry has issued a strategy for the establishment of offshore wind energy projects and various business models for the project development indicating the bidding trajectory for the installation of 37 gigawatt capacity. As on date, offshore wind में एक एस्टिमेट किया गया है कि इसमें 37 gigawatt बिजली का उत्पादन हो सकता है। क्या हमें इसको tap नहीं करना चाहिए? इसके लिए हमने काम शुरू किया है। The initial phase of MNRE identified zones, each of Gujarat and Tamil Nadu, is to exploit the wind energy potential. The Government has approved it. चूँकि यह नया है, इसलिए इसमें investment ज्यादा होता है। इसके लिए पोर्ट को अपग्रेड करना पड़ता है, उसके लिए बड़े-बड़े equipment आते हैं। पोर्ट अपग्रेडेशन के लिए और overall VGF के लिए we have allocated and already, इसका process शुरू हो गया है, Rs. 7453 crores including Rs. 6853 crores for installation and commission of one gigawatt. Sir, 500 megawatt each in Gujarat and Tamil Nadu in 2025-26. इसके साथ ही गुजरात ने 4.50 रुपए में और तमिलनाडु ने 4 रुपए में power off-take के लिए agreement किया है और उसके लिए tender बुलाया गया है। इस पर काम शुरू हो जाएगा। The Ministry through the Solar Energy Corporation has served the global bids for bidding and commissioning and operating of 4000 megawatt of offshore wind power projects on the

coast of Tamil Nadu and issued first tender for leasing out the seabed for the development of 4 gigawatt offshore wind power project in line with the offshore wind energy strategy.

सर, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि PM *Surya Ghar*, PM-KUSUM, green hydrogen, offshore wind energy - इन सभी योजनाओं में काम हो रहा है। यह पहली बार है कि इन सभी में काम हो रहा है। This is the first time ever we are in all the sectors. रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के तहत जो un-tapped है, उसके लिए हमने काम करना शुरू किया है। इसमें challenges हैं, मैं इससे इंकार नहीं करता हूँ। But the challenges have to be met by both the State and the Centre together, क्योंकि land देना State Government के हाथ में है। चूंकि हमें काम करना है, इसलिए हम स्टेट्स के साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि one more scheme that was added to that was of Polysilicon wafer cells, PV models. We have already processed a scheme of Rs.24,000 crores for that. This is quite optimistic. इस तरह, बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे projections के अनुसार काम आगे बढ़ रहा है।

मैंने already कई विषयों के बारे में बता दिया है, लेकिन यहां जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में अब मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। सबकी तरफ से एक प्रश्न आया थाकि as to whether we can achieve the target of 500 gigawatt. That I have replied. यह भी कहा गया कि "पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना" में मुफ्त कैसे होता है, यह एक जुमला है। यह जुमला नहीं है, बल्कि जो फैक्ट है, वह मैंने बताया है। Renewable energy installed capacity has been increased; that I have also explained, क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछा गया था।

मैं investment के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि FDI equity inflow from 615.95 million dollars in 2014--under ten years of Modi Government--has increased to 3,764.06 million dollars during 2023-24, which is an increase of 3,148.11 USD. इसमें इतनी बड़ी मात्रा में FDI आ रहा है।

IREDA loan distributed also has been increased. In 2014, Rs.14,390 crores were disbursed and now, in 2024, Rs.1,25,916 crores have been disbursed. See the difference. सर, इसमें जमीन-आसमान का फर्क है। ये Indian companies हैं, इनको loan लेकर काम करना पड़ता है। इसमें Rs. 1,11,597 crores का फर्क है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें काम शुरू हो गया है।

RE investment in 2014 was Rs.3 lakh crores. In 2024, it is Rs.7.5 lakh crores. मैं Green Hydrogen के बारे में बता चुका हूँ। रंजीत रंजन जी ने वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्रश्न उठाया था। The Ministry of Environment and Forests has issued guidelines in this regard that everybody has to follow because wastage कहीं भी होती है। जब हम online transaction करते हैं, computer वगैरह का भी e-waste generate होता है। आप कुछ भी करते हैं तो सभी जगह waste generate होता है। Rules are in place for waste generation, which are applicable to

solar photo-voltaic modules or panels or cells waste generated up to the year 2034-2035 as per the guidelines laid down by the Central Pollution Control Board. The majority of the wind turbine components are made up of the metals which can be recycled. इस पर भी हमने प्रोग्राम बनाया है।

One more important point was raised that India is also working on storage also. जैसा मैंने कहा, 12,000 मेगावॉट का storage हम लद्दाख में कर रहे हैं। Besides that, India is also making progress in the energy storage sector having currently achieved around 114 megawatt grid-scale battery storage and 4,500 megawatt pumped storage. उसके साथ ही Ministry of Power से - अभी जो bids हम कर रहे हैं, हमारी जो 4-5 renewable energy implementing agencies है, वे round the clock - अगर आप renewable energy उत्पादन करते हैं, उसके लिए bid करते हैं, for that, tenders have to be floated and that work is going on and VGF Scheme for the development of 4,000 megawatt per hour of Battery Energy Storage System projects by 2031 with the financial outlay of Rs.3,760 crores and support up to 40 per cent of the capital cost in the VGF has been allowed and that process is also on, Sir. यहां land acquisition के बारे में बात हुई। रंजीता ने कुछ विषय उठाया। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हर एक प्रोजेक्ट में land acquisition का इश्यु है। इसमें भी इश्यु आ रहा है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ coordinate कर रहे हैं। वह चाहे इस पार्टी का हो या उस पार्टी को हो, हम तो coordinate कर रहे हैं। And, it is very unfortunate that some of the Members only see the progress in the other countries. हम भी equally कर रहे हैं। RE sector में हमारा जो achievement है, उसके लिए दुनिया हमको मान रही है। India is in the forefront of this. दुनिया मान रही है, लेकिन यहां कुछ लोग criticism ही करते हैं, अगर हम कुछ सजेशंस देते हैं, तो constructive criticism होता है। अगर उनकी तरफ से कुछ सजेशंस आते हैं, तो हम उन पर विचार करते हैं। In spite of political difference, हमें तो इसमें काम करना है, क्योंकि this is the future. हमारे children ही नहीं, बल्कि grand children, great grand children के लिए हमको इस earth को, इस भूमि को safe रखना है, तो renewable energy must है। हम सबको मिलकर काम करना है। We have to work together. For green hydrogen, I have already explained, 23 bids have been received in Tranche 2 and the Government has imposed the basic custom duty on the import of solar PV cells and the modules. ...*(Interruptions)*... Therefore, इनके कालखंड में, the Government has imposed the basic custom duty on the solar PV cells and modules. हमारे समय में rupees twenty four thousand crore में cells and modules manufacturing के लिए काम शुरु हुआ है। And with respect to cells, I would like to inform that supply chain with respect to the modules, we have now sufficient capacity of 60 gigawatt, which is likely to increase to 100 gigawatts. As far as our modules is concerned, now, we have 60 gigawatt and likely to increase 100 gigawatt in coming three

years. For that, there is a viability gap funding. With respect to cells, we have 6 gigawatt now, which is likely to increase 18 gigawatt. And in the few months, it is going to become 18 gigawatts. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः अन्य किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

SHRI PRALHAD JOSHI: It is going to become 25-30 gigawatts by March, 2025. इस टारगेट को मन में रखकर काम चल रहा है। इसमें ऑलरेडी 6 गीगावाट हुआ है, 18 गीगावाट बहुत जल्द हो जाएगा और मैं cells के बारे में बात कर रहा हूं कि वह मार्च, 2025 तक 25-30 gigawatt हो जाएगा। Further, to provide level playing fields and domestic manufacturers in the solar manufacturing, the Government has imposed the basic custom duty on import of solar PV cells and modules, solar glass, copper, interconnect, etc. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि Congress and the INDIA Alliance should understand the difference between their time, when everything was imported. Everything was imported. जहां तक पी.वी. मॉड्यूल का सवाल है, 2 गीगावाट का भी नहीं बनता था, अभी 60 गीगावाट का शुरू हो गया है।

As per IRENA's International Renewable Energy and jobs: Annual reviews; job creation has nearly doubled from 4.37 lakh in 2014 to almost nearly 10 lakh in 2022. This is double. Moreover, the schemes like PM Surya Ghar Yojana, 17 lakh direct jobs will be created in manufacturing, logistics supply chain, installation and O&M. इसके लिए भी ट्रेनिंग के लिए PM Surya Ghar, PM Kusum इन सबको मिलाकर for training, there is around Rs. 700 crores and apart from that skill development मंत्रालय भी इसमें काम कर रहा है। Another thing is that from 2000 to 2015, 11,542 persons were trained and skilled, whereas from 2015 to 2024, more than 61,170 were skilled. And out of those 61,000 skilled persons, 27,472 persons got employment. उनको जॉब मिली और increase of GST के बारे में बताया। Sir, GST rate on renewable equipment was revised from five per cent to 12 per cent on the recommendation of GST Council in its 45th meeting held on 17.5.2021. The GST Council is a joint forum of Centre and State. This correction in rate is helping the domestic manufacturers of the renewable energy...एक सेक्टर के डिमांड के आधार पर किया है। यह हमने नहीं किया है, स्टेट के लिए रिक्वेस्ट आई थी और स्टेट ने रिकमंड किया है। Sir, this correction in rate is helping the domestic manufacturers of the renewable energy equipment through the better utilization of the input tax credit, making them more competitive both domestically compared to the imports. That is why it is done. It was demand of the sector and that is why it is done. ...*(Interruptions)*... सर, जीएसटी काउंसिल भारत सरकार के कहने पर नहीं चलती है। उसमें सभी स्टेट्स शामिल रहती हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, he is not yielding.

SHRI PRALHAD JOSHI: The Ministry is implementing the renewable energy research and technology development program with a total budget of Rs. 220 crores for the year 2021-2022 to 2025-26. Through this House, I would like to apprise the entire country that we are proud of our scientists who have made a considerable progress in R&D of the renewable energy. मैं आपको बताना चाहता हूं कि there is development of high-efficiency perovskite solar cells of 25.8 per cent efficiency and 30 per cent efficiency of Silicon-Perovskite Tandem solar cells by NCPRE-IIT Bombay. This has been developed domestically, Sir. यह R&D का प्रभाव है। The CSIR and National Physical Laboratory developed the first kind of primary standard solar cell facility in the country with the lowest calibration of uncertainty in the world, which would help the solar manufacturing industry to achieve significant cost saving. As a major impetus, NTPC launched India's first hydrogen bus. The trial of India's first hydrogen bus was held in Leh. इसका ट्रायल शुरू हो गया है। Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARCI) has established first of its kind, automated assembly line in fabrication of proton exchange membrane. On this technology, PEM fuel cell is developed in the country for utilising the indigenous component. भारत के component यूज़ करके, PEM टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने अभी first of its kind, automated assembly line for the fabrication of PEM शुरू की है। इसके साथ ही मैं PM Kusum के बारे में कहना चाहता हूं। सर, मैं लास्ट में पांच मिनट में कुछ कहना चाहता हूं। Hon. Member of the Congress Party raised several issues. मैंने GST के बारे में बताया, GST Council के बारे में बताया। महोदय, मैंने सूर्य घर योजना के बारे में बताया। महोदय, 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के बारे में कहा गया। ..(**व्यवधान**).. 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के बारे में 'मोदी-चीनी भाई-भाई' कहा गया। सर, ये लूज़ कमेंट्स अच्छे नहीं हैं। हमें भी इन्हें remind कराना पड़ेगा, We will have to remind them what happened in 1962. It is because of your failure. 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के कारण, we lost around 38,000 sq. kms. of land and we just surrendered before China! We just surrendered before China! What happened when Tibet was encroached by China? उन लोगों को राशन भेजा गया। ..(**व्यवधान**).. This is your track record! एक रिकॉर्ड रखकर, जिस पार्टी में ..(**व्यवधान**).. सर, इन लोगों ने आरोप लगाया है। मैं यह अपने आप नहीं कह रहा हूं। सर, इन लोगों ने आरोप लगाया है। 'मोदी-चीनी भाई-भाई' किसने कहा है? ऐसा इन लोगों ने कहा है। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये लोग ही हैं, जिस पार्टी ने अपनी पार्टी चलाने के लिए चाइना से चंदा लिया था। वे लोग हमें सिखाते हैं! They have availed donation from China for their party! और जिन्होंने एमओयू बनाया, और जब अपोजिशन में थे, तब भी छुप-छुप

कर किससे मिले थे? Chinese Ambassador से मिले थे। ये लोग हमें सिखाते हैं! ये लोग जो बोल रहे हैं, इन्हें आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए।

महोदय, आम आदमी पार्टी के एक मैम्बर ने कहा कि चाइना जीरो से हीरो बन गया। इनकी पार्टी की सोच देखिए कि ये कहते हैं कि चाइना जीरो से हीरो बन गया। ..(**व्यवधान**).. यह आम आदमी पार्टी के सदस्य ने कहा है।..(**व्यवधान**).. सर, यह आम आदमी पार्टी के सदस्य ने कहा है, मैंने अपने आप नहीं कहा है, मैं अपने आप कुछ नहीं कह रहा हूं। यदि जीरो से हीरो बोलेंगे तो क्या China को appreciate करना है इनका काम है? ..(**व्यवधान**)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रह्लाद जोशीः मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने चाइना से चंदा लिया, वे उनके साथ बैठकर हमें पाठ सिखा रहे हैं! महोदय, but doesn't acknowledge and recognize the heroics. जो काम हुआ है, मैं वह बताना चाहता हूं कि हमने सोलर में फोर्थ पोजिशन से ..(**व्यवधान**).. हम फिफ्थ पोजिशन में ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में पहुँचे हैं। ये उसके बारे में एप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, स्टेट में जो फेल्योर आया है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं।..(**व्यवधान**)..

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): उपसभापति जी. ..(**व्यवधान**)..

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, hon. LoP wanted to say something. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रह्लाद जोशीः महोदय, Mr. Pathak, Co_2 reduction led to renewable energy... ...*(Interruptions)*... But, I cannot realize why you cannot achieve both these goals. ...*(Interruptions)*... What is impossible for them is मोदी के लिए पॉसिबल है, मुमकिन है। Sir, he raised the issue of India's solar energy. सर, हम 2.8 से 85 गीगावॉट तक पहुँच गए हैं।

श्रीमती रंजीत रंजनः *

श्री प्रमोद तिवारीः *

श्री शक्तिसिंह गोहिलः *

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...केवल मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)..

श्री प्रह्लाद जोशीः सर, उन्होंने कहा। We don't mind constructive criticism, पर ऐसा बोलेंगे, तो हमें रिप्लाई देना ही पड़ेगा।

(*At this stage some hon. Members left the Chamber.*)

सर, दो कंपनी को देते हैं, तीन कंपनी को देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लिमिटेड लोग हैं। सर, देखिए इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये आरोप लगाते हैं, ये बिना तथ्य के आधार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में सुनने की क्षमता नहीं है, बाद में भाग जाते हैं। सर, मैं बता रहा हूं, to keep it on record, जाने के पहले सुनकर जाइए। Sir, for Solar PV panels, there are 93 manufacturers in the country. रंजीत रंजन जी, समझ लीजिए कि there are 93 manufacturers in the country and enlisted in MNRE's approved list of manufacturers. मैन्युफैक्चरर्स में जो एप्रूव्ड है, वह 93 है। सोलर पीवी सैल में 9 मैन्युफैक्चरर्स हैं।...(**व्यवधान**)....

श्री उपसभापतिः सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। .(**व्यवधान**)..

SHRI PRALHAD JOSHI: For copper interconnect, there are about more than 12 manufacturers. For encapsulants, there are 10 manufacturers. सबको ऑर्डर मिल रहे हैं। सर, ये क्या बात करते हैं! जॉब क्रिएशन के बारे में डीएमके के सदस्य ने सवाल उठाया था, मैंने उसका उत्तर दे दिया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. आप धैर्य से माननीय मंत्री जी को सुनिए।

श्री प्रहलाद जोशीः सर, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलता हूँ। ये उठकर चले गए हैं। जब ये उठकर चले जाते हैं, तो हमारा उत्साह भी कम हो जाता है।

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करिए।

श्री प्रहलाद जोशीः महोदय, देरेक ओब्राईन जी ने इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के बारे में सवाल उठाया। सर, मैं कहता हूँ कि from 1947 to 2014, not a single international organization was conceptualized and set up to be headquartered in India. This is the first time, under the

visionary leadership of the hon. Prime Minister, International Solar Alliance का हेडक्वार्टर भारत बन गया है। And, India co-funded ISA to promote growth of solar energy in the world and increase the international cooperation. सागरिका घोष जी ने कहा कि gap between the vision, यानी सपना and reality, यानी हकीकत। जो सपनों की बात करते हैं, they should know that since 2014, देश में दुस्वपन देखने का दौर खत्म हो गया है। So, I would like to say, हमें सपना देखने के लिए भी धैर्य चाहिए। TMC shall dream but we realize them. हम सपनों को साकार करते हैं। हम सपनों के सौदागर नहीं हैं। हम सपनों को दिखाते भी हैं और साकार भी करते हैं। यह मोदी जी की सरकार है। इसके साथ ही, कंसल्टेशन की बात की कि आप कंसल्ट नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का जो भी सदस्य है, आप सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं, ये भाग गए, लेकिन एकाध इधर भी तो होगा। आप सुनिए और जाकर वेस्ट बंगाल में बोलिएगा। सर, जब भी कंसल्टेशन के लिए मीटिंग बुलाते हैं, हम तो इंडस्ट्रीज़ के साथ हर महीने मीटिंग करते हैं, लेकिन जब हम कंसल्टेशन करने के लिए, सजेशन लेने के लिए और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए - - सर, जब हम पोलिटिकल लेवल पर बुलाते हैं, मंत्री के लेवल पर बुलाते हैं, तब ठीक है, यह इनकी पोलिटिक्स है, लेकिन ये ऑफिसर्स से भी नहीं मिलते हैं। हम कहाँ से कंसल्ट करें? हम मीटिंग बुलाते हैं, almost, at regular intervals. वे लोग नहीं आते हैं और इधर आकर हमें भाषण देते हैं, हमें पाठ पढ़ाते हैं कि कंसल्टेशन करिए, कंसल्टेशन करिए, 'Think globally, act locally.' आप थोड़ा तो अपना घर सुधारिए। हमने आपको एक पार्क दिया था। A mega solar park of about 125 MW was given. पाँच वर्ष तक लैंड भी नहीं दिया, बात भी नहीं की और बात करने की कोशिश करें, तो रिस्पाँड भी नहीं करते हैं। ...(**व्यवधान**)... हमने 125 मेगावाट का सोलर पार्क वेस्ट बंगाल को दिया। The State failed to implement it. सर, ये बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर स्टेट में बहुत काम हो रहा है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। सर, मैं देवेगौड़ा जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया है, आशीर्वाद दिया है। जो उनके सजेशंस हैं, मैंने उन्हें पूरे ध्यान से सुना है। जो आपके अनुभव हैं, हम उनका पूरा उपयोग करेंगे और आपके सजेशंस का भी पूरा उपयोग करेंगे। Sir, days of darkness will not be forgotten. अभी तो इधर पावर कट हुआ है। एक्चुअली, मेरा काम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का है, लेकिन बीच-बीच में इधर पावर कट है, महाराष्ट्र में पावर कट हो रहा है, तमिलनाडु में पावर कट हो रहा है। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? जिन्होंने 60 सालों तक राज किया, उन लोगों ने सोचा नहीं। जैसे, मैंने पहले कहा, जब कोल का विषय था, तब कोल में उत्पादन नहीं किया, अब यह रिन्यूएबल का विषय है, तो रिन्यूएबल में काम नहीं करते हैं और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। सर, मैं लद्दाख के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं। Sir, I would like to thank all esteemed colleagues for their inputs. विकसित भारत का हमारा जो सपना है, aim है, उसके लिए ऊर्जा विकास हमारा मिशन है।

Sir, with these words, I am concluding. मैंने डीटेल में उत्तर देने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं, क्योंकि अभी वे बाहर चले गए हैं, लेकिन कहीं पर भी हों, वे सुन रहे होंगे, तो मैं अपील करता हूं कि Hydrogen की जो पॉलिसी है, Green Hydrogen की पॉलिसी है, उसे एनाउंस

करो, land का issue solve करो। जब consultation के लिए बुलाते हैं, तो आप आ जाइए, at least, bureaucrat के level पर आ जाइए। हम भारत को renewable energy में world leader बनाने का, जो सपना देख रहे हैं, उसके लिए हम आपका भी सहयोग मांगते हैं। सर, इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। आपके उत्तर के साथ 'Discussion on the Working of the Ministry of New and Renewable Energy' खत्म हुआ। अब स्पेशल मेंशन्स।

SPECIAL MENTIONS

Demand for de-notification of 3070 acres of land of Kedla-Dania area of Central Coal Field Ltd., a subsidiary of Coal India Ltd.

श्री खीरू महतो (बिहार)**:** महोदय, झारखंड प्रदेश के अंतर्गत कोल इंडिया लि० की अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड लि० स्थित है, जिसमें कोल बेयरिंग एरिया एक्ट (सी.बी.ए.) के तहत अधिसूचना संख्या 2082 दिनांक 30.06.1981 से तीन हजार सत्तर (3,070) एकड़ जमीन अर्जित की है, जो केदला, दनिया साइडिंग तक के लिए किया था, जिसमें 10 गांव अर्जित क्षेत्र में पड़ते हैं, वे गांव हैं - (1) बसंतपुर (2) पचंडा (3) कोतरे (4) हरदाग (5) रहावन (6) पचमो (7) पदनां टांड (8) विहाई महुआ (9) लईयो एवं (10) दनिया, जो झारखंड प्रदेश के दो जिलों में सर्वप्रथम रामगढ़ जिला एवं बोकारो जिला में पड़ते हैं। पहले तो जमीन के एक्विज़ीशन के बीस साल बाद सी.सी.एल. ने टाटा कंपनी को कोलियरी चलाने के लिए रुपये लेकर रजिस्ट्री कर दी, ...

श्री उपसभापतिः माननीय खीरू जी, वही पढ़िएगा, जो लिखा हुआ है।

श्री खीरू महतोः जी, सर। दस गांव के लिए अभी तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। आज 45 वर्ष हो रहे हैं, भू-विस्थापित गरीबी का दंश झेल रहे हैं।

अतः मैं भारत सरकार से देश एवं राष्ट्रहित में मांग करता हूं कि अर्जित भूमि 45 वर्ष हो गए हैं, जबकि कंपनी द्वारा काम नहीं किए जाने तथा पुनर्वासित नहीं करने के कारण रैयतों को जमीन का नियमत डी-नोटिफिकेशन कराया जाए, जिससे रैयत जमीन पर खेतीबाड़ी कर अपनी जीवनयापन कर सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर पुत्री का विवाह या अपने अपरिहार्य परिस्थिति में वे इसका लाभ ले सकें।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जो अप्रूव्ड टेक्स्ट है, आप वही पढ़ें।